



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 1973/वैशाख 6, 1895

No. 163]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 1973/VAISAKHA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 26th April 1973

S.O. 250(E)/18FB/IDRA/73.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 137(E)/18A/IDRA/73, dated the 12th March 1973, the management of the industrial undertaking known as M/s Hindustan Tractors Limited, Vishwamitri, Baroda (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking) has been taken over under clause (b) of sub-section (i) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 12th March 1973;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in the scheduled industry, namely Tractors:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 18-FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this order (other than those relating to liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from the date of issue of this order and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F.4/1/73-CUC.]

D K SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1973

का० आ० 250 (अ) 18बख/आई०डी०आर०ए०/73.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 137 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/73, तारीख 12 मार्च, 1973 द्वारा मैमर्स हिन्दुस्तान ट्रेडर्स लिमिटेड, विश्वामित्र, बड़ीदा नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम, कहा गया है) प्रबन्ध, उद्योग (विक्रम और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 12 मार्च, 1973 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है :

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग, अर्थात् ट्रेडर्स, में उत्पादन के परिणाम में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18-बख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के दायित्वों से संबंधित हैं) प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने

वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ।

[स० फा० 4/1/73-सी० मृ० सी०]

ही० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

